International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 04, October - December, 2019, pp.61-65

राजस्थान की ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के मध्य रोजगार के परिणामस्वरूप आए आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. वी.के. गुप्ता*
अभिषेक कौशिक**

सार

''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवताः''

मनुस्मृति में लिखी उपरोक्त पंक्तियां नारी की महता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन यथार्थ से पंक्तियों का कितना सरोकार है इस बात से हम सभी परिचित है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए स्त्रियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना अति आवश्यक है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि स्त्रियों को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि वे अपने से संबंधित फैसले लेने में स्वतंत्र हो। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया है कि रोजगार के फलस्वरूप उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन आया है। इसी संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यरत महिलाओं की तुलना करने का प्रयास किया है। इसके अध्ययन हेतु 4 चर (आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, स्वतंत्रता एवं जागरूकता) निर्धारित किए गए है। उपरोक्त चार चरों के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की तुलना को इस अध्ययन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

परिचय

राजस्थान एक विविधताओं से भरा प्रदेश है। यहां कला, संस्कृति, जलवायु एवं भौतिक स्वरूप आदि सभी में विविधता विद्यमान है। यहां का इतिहास काफी गौरवमयी रहा है। यहां के वीरों–वीरांगनाओं की गाथाओ का गुणगान पूरे देश भर में होता है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जयमल जी, कल्ला जी., हमीर देव, आल्हा जी भाटी, रावत रतन सिंह चुंडावत जैसे वीर एवं रानी पदमनी, हाड़ा रानी, पन्नाधाय जैसी वीरांगनाओ के उदाहरण भी इसी धरती से उपजे है। यही नहीं कालीबाई (वीर भील बालिका), अंजना देवी चौधरी (किसान आंदोलनों में सक्रिय), जानकी देवी बजाज (गांधी जी के साथ विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय) आदि महिलाओं के वीरता पूर्ण किस्से भी इसी धरती से उपजे हैं। वीरों की खान कहे जाने वाले इस प्रदेश में ऐसे वीरता पूर्ण किस्से आपको कदम कदम पर सुनने को मिल जाएंगे। इतिहास से आगे आए तो हम पाएंगे कि आजादी के बाद भी प्रदेश में ऐसी अनेक महिलाएं हुई है जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में अपनी पहचान देश–विदेश में स्थापित की है। उदाहरण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरूणा राय, राजनीति के क्षेत्र में सुमित्रा सिंह (प्रथम विधानसभा अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक), कमला बेनीवाल (त्रिपुरा, मिजोरम एवं गुजरात में राज्यपाल का पद सुशोभित कर चुकी) खेल के क्षेत्र में कृष्णा पूनिया, शूटिंग के क्षेत्र में अपूर्वी चंदेला, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में बाड़मेर की रूमा देवी (2018 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित), राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुकी कालबेलिया नृतकी गुलाबो, बीएसएफ की पहली महिला असिस्टैंट कमांडेंट तनुश्री पारीक इत्यादि महिलाओं ने राजस्थान का नाम देश विदेश में रोशन किया है।

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

- **रोजगार** – जब कोई व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया संपन्न करता है तो इसे हम रोजगार कहते हैं।
- **शहरी महिलाएं** – ऐसी महिलाएं जो शहर में निवास करती है अथवा शहर में रहकर आजीविका अर्जित कर रही है।
- **ग्रामीण महिलाएं** – ऐसी महिलाएं जो गांव में निवास करती है अथवा गांव में रहकर आजीविका अर्जित कर रही है।

शोध प्रविधि

इस शोध पत्र के लिए शोधार्थी के द्वारा मुख्य रूप से प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया गया है। समंकों का संग्रहण करने के लिए शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से लघु–कुटीर उद्योगों में कार्यरत महिलाओं से साक्षात्कार लिए गए है। उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति जानने के लिए उनसे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, स्वतंत्रता एवं जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए। एकत्रित किये गए समंकों से SPSS के माध्यम से t टेस्ट द्वारा परिणाम ज्ञात किए गए हैं। यह शोधपत्र सर्वेक्षण शोध विधि पर आधारित है।

अध्ययन में प्रयुक्त चर

- **आर्थिक स्थिति** – आर्थिक शब्द **"अर्थ"** में **"इक"** प्रत्यय लगाने से बना है। यहां **अर्थ** से तात्पर्य धन से है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति से तात्पर्य उत्तर दाता के पास उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से है जिससे कि अमीरी और गरीबी का निर्धारण होता है।
- **सामाजिक स्थिति** – आर्थिक की भांति सामाजिक शब्द भी **"समाज"** में **"इक"** प्रत्यय जोड़कर बना है। समाज से तात्पर्य उस परिवेश से है जहां हम रहते हैं। हमारे आस पास के लोगों का समूह हमारे लिए समाज कहलाता है। सामाजिक स्थिति से तात्पर्य समाज में लोगों के समक्ष हमारे रहन–सहन के स्तर से है। समाज में हमें किस नजरिए से देखा जाता है यह हमारी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है।
- **स्वतंत्रता** – स्वतंत्रता से तात्पर्य इस बात से है कि महिलाएं स्वयं की आय खर्च करने, घर से बाहर जाने का निर्णय स्वयं ले सकती है अथवा इसके लिए उसे पति या परिवार पर निर्भर होना पड़ता है।
- **जागरूकता** – जागरूकता से तात्पर्य इस बात से है कि उत्तरदाता महिला को अपने अधिकारों एवं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की कितनी जानकारी है।

अध्ययन के उद्देश्य

- रोजगार के परिणाम स्वरूप राजस्थान की शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में आए परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

$\mathbf{H_1}$ शहरी एवं ग्रामीण रोजगारशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर होता है।

$\mathbf{H_0}$ शहरी एवं ग्रामीण रोजगारशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं होता है।

$\mathbf{H_1}$ शहरी एवं ग्रामीण रोजगारशुदा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर होता है।

$\mathbf{H_0}$ शहरी एवं ग्रामीण रोजगारशुदा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं होता है।

साहित्य समीक्षा

Kavita Jane Crasta और Sangeetha Shridhar (2019) ने अपने शोध पत्र "Problems of women entrepreneurs in Shivamogga district" में स्पष्ट किया है कि जो कार्य पुरूष कर सकता है महिलाएं उसे बेहतर ढ़ंग से कर सकती हैं। शोधार्थीयो नें शिव मोगा जिले में महिला उधमियो के समक्ष आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला है। शोधार्थीयो के अनुसार महिला उधमियो को पारिवारिक बंदिश, शिक्षा का अभाव, कच्चे माल की कमी, कठोर प्रतिस्पर्धा, जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव, मध्यस्थ द्वारा शोषण इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शोधार्थी के अनुसार सरकार व व्यापारिक बैंकों को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, रियायती दर पर कच्चा माल उपलब्ध करवाना चाहिए। इत्यादि

डॉ. नरेन्द्र सिंह (2018) ने अपने शोध पत्र ''महिला सशक्तिकरण और नई पीढ़ी'' में बताया है कि महिलाओं को सशक्त बनने के लिए महिलाओं को अपनी पूर्व धारणा बदलने की आवश्यकता है "कि वह कमजोर है और उन्हें कोई भी धोखा दे सकता है। इसकी बजाय उन्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि उनमे पुरूषों से अधिक शक्ति है और वे पुरूषों से अधिक बेहतर कर सकती हैं।"

के.एम. सीमा (2017) नें अपने शोध पत्र ''राजस्थान में महिला एवं आर्थिक सशक्तिकरण'' में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर दिया है। शोधार्थी के अनुसार महिला आर्थिक सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को स्वयं की एवं पारिवारिक आय खर्च करने की स्वतंत्रता से है। उनके अनुसार रोजगार से महिलाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जिस प्रकार से महंगाई एवं प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है एवं परिवार बिखर रहे हैं ऐसे में महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण अनिवार्य हो जाता है।

रविंद्र कुमार (2015) ने अपने शोध पत्र ''महिला सशक्तिकरण पर गैर सरकारी योजनाओं का योगदान (जयपुर जिले के विशेष संदर्भ में)'' मे शोधार्थी ने राजस्थान के जयपुर जिले में संचालित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का अध्ययन एवं सर्वेक्षण कर महिला सशक्तिकरण में इन संगठनों की भागीदारी की जांच करने का प्रयास किया है। शोध पत्र में शोधार्थी ने महिला सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं–

- महिलाओं को शिक्षित करना।
- महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान करवाना।
- निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को पुरूषों के समान भागीदारी हेतु प्रेरित करना।
- गैर सरकारी संगठनों को सुझाव देना कि वे महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु शिविर आयोजित करें, खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाएं, संगठन को रजिस्टर्ड करवाएं, लेखा–जोखा स्पष्ट रखें। इत्यादि।

डॉ. जनक सिंह मीणा (2015) ने अपने एक आलेख ''महिला मानवाधिकारों का वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य'' में महिलाओं के अधिकारों की वैश्विक एवं भारतीय स्तर पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि विश्व की आधी जनसंख्या में महिलाएं हैं और कुल श्रमिक वर्ग के एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं लेकिन फिर भी विश्व की कुल आमदनी में मात्र 10 प्रतिशत हिस्सा तथा कुल संपत्ति में 1 प्रतिशत से भी कम उनके हिस्से में आता है। वहीं कुल श्रम बल में उनकी हिस्सेदारी लगभग दो तिहाई है लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें उनके पूरे अधिकार नहीं मिल पाते हैं।

मानचंद खंडेला (2008) ने अपनी पुस्तक ''महिला सशक्तिकरण'' के प्रथम अध्याय में महिलाओं द्वारा झेले जा रहे विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालते हुए उनके संबंध में बनने वाले कानूनों और उनकी असफलताओं पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के पक्ष में इतने कानून बनने के बावजूद भी इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इसके लिए सरकार को पुरानी कुप्रथाओं पर सीधा प्रहार करने की व निश्चित कानून बनाने की आवश्यकता है तभी स्थिति को सुधारा जा सकता है।

अध्ययन के परिणाम

शोधार्थी ने मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी परीक्षण के आधार पर उनके निष्कर्ष निकाले हैं।

सांख्यिकीय मान

निवास स्थिति		संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	प्रमाप विचलन (S.D.)	प्रमाप त्रुटि मध्यमान
आर्थिक स्थिति	श.	149	2.6966	.33011	.02704
	ग्रा.	138	2.7159	.34919	.02973
सामाजिक स्थिति	श.	149	1.6779	.62689	.05136
	ग्रा.	138	1.9493	.76723	.06531
स्वतंत्रता	श.	149	2.8121	.47824	.03918
	ग्रा.	138	2.8261	.42090	.03583
जागरूकता	श.	149	2.2003	.51585	.04226
	ग्रा.	138	2.0048	.49365	.04202

श.–शहरी, ग्रा.–ग्रामीण

स्त्रोत – प्राथमिक समंकों पर आधारित

स्वतंत्र प्रतिदर्श परीक्षण

(Independent Sample Test)

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	dt	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
						P मान			Lower	Upper
आर्थिक स्थिति	Equal variances assumed	6.845	.009	-.481	285	.631	-.01930	.04010	-.09823	.05963
सामाजिक स्थिति	Equal variances assumed	33.845	.000	-3.292	285	.001	-.27142	.08245	-.43371	-.10913
स्वतंत्रता	Equal variances assumed	.204	.652	-.263	285	.793	-.01401	.05335	-.11902	.09101
जागरूकता	Equal variances assumed	.184	.668	4.781	285	.000	.28544	.05970	.16793	.40294

स्त्रोत – प्राथमिक समंकों पर आधारित

अध्ययन के परिणाम

उपरोक्त चार चरों में शहरी व ग्रामीण महिलाओं में उनके निवास स्थिति के आधार पर क्या अंतर पाया गया इसके परिणाम नीचे दिए जा रहे हैं–

- **आर्थिक स्थिति** – आर्थिक स्थिति के आधार पर पाया गया कि शहरी व ग्रामीण महिलाओं का P मान (.631) है जो कि पूर्व निर्धारित P मान .05 से अधिक है। अतः इस आधार पर शहरी व ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। अर्थात ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार की महिलाओं का मानना है कि रोजगार से उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है।
- **सामाजिक स्थिति** – सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पाया गया है कि शहरी व ग्रामीण महिलाओं का P मान (.001) है जो कि पूर्व निर्धारित P मान .05 से कम है। अतः इस आधार पर शहरी व ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर पाया गया है। दोनों प्रकार की महिलाओं के औसत जवाब लगभग तटस्थ है। अर्थात् इन दोनों प्रकार की महिलाओं का मानना है की रोजगार से उनकी सामाजिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन ग्रामीण महिलाओं के विचार शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक सकारात्मक है।
- **स्वतंत्रता** – स्वतंत्रता के संबंध में पाया गया कि शहरी व ग्रामीण महिलाओं का P मान (.793) है जो कि पूर्व निर्धारित P मान .05 से अधिक है। अतः इस आधार पर शहरी व ग्रामीण महिलाओं में स्वतंत्रता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। दोनों प्रकार की महिलाओं में स्वतंत्रता की स्थिति सकारात्मक है।
- **जागरूकता** – जागरूकता के संदर्भ में शहरी व ग्रामीण मतिहलाओं का P मान (.000) है जो कि पूर्व निर्धारित P मान .05 से कम है। अतः इस आधार पर शहरी व ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सार्थक अंतर पाया गया हैं। इसमें शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक जागरूक है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि रोजगार से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है चाहे वह एक ग्रामीण महिला हो अथवा शहरी महिला। लेकिन आर्थिक स्थिति में परिवर्तन सामाजिक स्थिति में परिवर्तन की तुलना में अधिक आया है। दरअसल सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए समाज की मानसिकता को बदलना आवश्यक है। जो कि तुलनात्मक रूप से थोड़ा कठिन कार्य है। छोटे से

उदाहरण से बताना चाहूंगा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिलाएं छोटे–मोटे काम धंधों के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करती है। उदाहरण के लिए दरी निर्माण, टोकरी निर्माण कार्य इत्यादि। ऐसे में काम करने से उन महिलाओं के परिवार की आमदनी तो स्वाभाविक रूप से बढ़ती ही है और उनकी एक–दो आवश्यकताएं और भी पूरी होने लग जाती है। उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव भी आ जाता है। लेकिन यह बदलाव इतना बड़ा नहीं होता है जो समाज की सोच को, महिलाओं के प्रति उनके रवैए को बदल सकें। इसलिये महिलाओं को ऐसे रोजगार से जोड़े जहां उनकी आमदनी बढ़े एवं उनकी आवश्यकता पूरी होने के साथ–साथ उनका जीवन स्तर, सामाजिक स्तर भी ऊँचा उठे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- ''महिला सशक्तीकरण और नई पीढ़ी'', डॉ. नरेन्द्र सिंह (2018), इण्डियन जर्नल ऑफ रिसर्च।
- ''राजस्थान में महिला आर्थिक सशक्तीकरण'' के.एम. सीमा (2017), इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ अपलाइड रिसर्च।
- ''महिला सशक्तीकरण पर गैर सरकारी योजनाओं का योगदान'' (जयपुर जिले के विशेष संदर्भ में) रविन्द्र कुमार (2015) AIJRA Vol.II Issue IV, (www.ijcms2015.co.)
- ''महिला मानवाधिकारों का वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य'', डॉ. जनक सिंह मीणा (2015), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
- ''महिला सशक्तिकरण'' मानचंद खंडेला, अरिहंत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2008
- "Problems of Women Entrepreneurs in Shiv Amogga District", Kavita Jane Crasta And Sangeetha Shridhar (2019), International Research Journal of Commerce and Law.
- patrika.com
- thebetterindia.com.

❖◆❖